

an>

Title: Need to provide adequate compensation to farmers who suffered loss due to hailstorms and untimely rains in Maharashtra.

श्री राजू शेटी)हातकणगले:(महाराष्ट्र के किसानों के पीछे नैसर्गिक आपदा और सुलतानी आपदा लगातार हाथ धोके पड़ी है इससे छूटने के लिए किसानों को आत्महत्या के लिए फाँसी का फंदा अपने गले को लगाना पड़ रहा है। किसानों को एक तरफ अच्छे दिन के सपने दिखाए गए तो दूसरे तरफ कर्ज माफी का वायदा किया गया तो तीसरी तरफ एम.एस.पी .के तहत लागत से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का वायदा वर्तमान बजट में किया गया जो कि यथार्थ के धरातल पर कभी नहीं उतरता। यह सब चीजें किसानों का आक्रोश बढ़ाने वाली है।

बीते दो सप्ताह पहले महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में जो बेमौसम बारिश और धुँआधार ओलावृष्टि हुई उसने तो किसान के मुँह में आने वाला निवाला ही नहीं छीन लिया बल्कि किसान को पूरी तरह से संकट में डाल दिया है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के तहत एक लाख 87हजार हैक्टेयर क्षेत्र में जो खड़ी फसले थीं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। इसके साथ-साथ सात लोगों की और कई जानवरों और पशु पक्षियों की भी जान चली गई। जालना, अमरावती, नागपुर और अन्य जिलों के तहसील में मौसम्बी, अंगूर, संतरा आम के बगीचे क्षतिग्रस्त हो गए।

इस संकट की घड़ी में केन्द्र और राज्य सरकार को डट के किसानों के पीछे खड़ा रहने की जरूरत है, लेकिन महाराष्ट्र के कृषि मंत्री जी ने सरकार की तरफ से राहत की घोषणा की है उसमें बगैर सिंचाई वाले किसानों को)बंजर (प्रति एकड़ 2400रु) .चौबीस सौ रुपये (और सिंचाई वाले किसानों को)इरीगेशन (प्रति एकड़) 5400पांच हजार चार सौ रुपये (देने का एलान किया, और फल वाले बगीचे वाले किसानों को प्रति एकड़ 14 हजार 720रुपये देने का एलान किया जिसने प्रधानमंत्री

फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम भरा हो, तो उसको बीमा कंपनी की तरफ से यह पैसे मिलेंगे। लेकिन जिसने फसल बीमा निकाला नहीं उन किसानों को राज्य सरकार की तरफ से सिर्फ 7 हजार 200रुपये प्रति एकड़ दिये जाने का एलान किया। यह तो किसानों के जख्म पर नमक और मिर्च छिड़कने जैसा है। इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार से 200करोड़ रुपये की मदद मांगी गई है।

बीते 3 या 4बरसों से जैसे महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार आई है तब से हर साल किसानों को नैसर्गिक आपदा ही नहीं तो सुलतानी संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। और उसमें बढ़ोतरी हो रही है। अब की बार धुँआधार ओलावृष्टि ने जो हद कर दी है। इसलिए सरकार को एन.डी.आर.एफ .और बीमा कंपनियों के साथ मिल कर किसानों की मदद करनी चाहिए और इसके साथ मेरी यह मांग है और विनती है कि बंजर भूमि वाले किसानों के प्रति एकड़ 15हजार रुपये और सिंचाई वाले किसानों को 25हजार रुपये प्रति एकड़ से मुआवजा देना चाहिए इसलिए केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को राहत कोष से 500करोड़ रुपये देने की सख्त जरूरत है।

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m. on Thursday, 8th March, 2018.

12 08 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 8, 2018/Phalgun 17, 1939 (Saka).

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.